राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 17906/2018

श्रीमती कन्या देवी पत्नी श्री भंवर लाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी गांव-गोडा बीजा, वाया-बागड़ी नगर, तहसील-सोजत, जिला-पाली।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर के माध्यम से।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, पाली।
3. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, पंचायत समिति- सोजत, पाली।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मंसूर अहमद सिद्दीकी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री ललित पारीक

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

16/05/2024

1. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को अपने पति के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन पर निर्णय लेने, उसे स्वीकार करने और ब्याज सहित पारिवारिक पेंशन सहित परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की है।

2. संक्षेप में कहा जाए तो, यह याचिका असाधारण परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ता के पति, जो प्रतिवादी द्वारा नियोजित थे, सेवा में रहते हुए ही साधु बन गए, तथा परिवार, सामाजिक जीवन या अपनी नौकरी में कोई रुचि नहीं दिखाई। याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों ने उन्हें सामाजिक जीवन में पुनः शामिल करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि उन्होंने भौतिकवादी और सांसारिक मामलों में सभी रुचि खो दी।

2.1. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके पति ने उसे सभी कानूनी रूप से देय सेवा लाभों के लिए अपनी लिखित सहमति दी थी। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने एक अधिकृत व्यक्ति के रूप में यह याचिका दायर की है।

2.2. याचिका दायर करने के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पति 1979 में वरिष्ठ शिक्षक के रूप में सेवा में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने अस्वस्थता के कारण 12.11.2008 (अनुलग्नक 3) और फिर 24.11.2014 (अनुलग्नक 4) को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

2.3. 28.11.2014 को, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसका आवेदन निदेशक को भेज दिया। हालाँकि, प्रतिवादी प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई के बिना काफी समय बीत गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने न्याय की मांग करते हुए वकील के माध्यम से 30.07.2018 को एक कानूनी नोटिस भी दिया, जिसका भी कोई जवाब नहीं मिला।

2.4. याचिकाकर्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता का परिवार भूख से मर रहा है और उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

3. जवाब में बचाव पक्ष का कहना है कि अधिकारियों को याचिकाकर्ता के पति के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन पर निर्णय लेना है और कानून के अनुसार परिणामी लाभ प्रदान करना है।

3.1. रिट इसलिए संधारणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पति की सेवाएं वास्तव में सीसीए नियम, 1958 के अनुसार दिनांक 20.08.2015 के कार्यालय आदेश (अनुलग्नक आर/1) द्वारा समाप्त कर दी गई थीं।

3.2. सेवा से बर्खास्तगी के कारण याचिकाकर्ता के पति की पिछली सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 23 के तहत जब्त कर ली गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता का अपने पति की वर्तमान स्थिति के कारण पारिवारिक पेंशन का दावा निराधार है।

3.3. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 2003-04 से अपने पति को भिक्षु घोषित करने वाले कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, और प्रतिवादियों को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे उसका पारिवारिक पेंशन का दावा निराधार हो गया है।

3.4. किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन का दावा नहीं कर सकती क्योंकि उसका पति जीवित है। पारिवारिक पेंशन केवल कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में दी जाती है, जो कि यहां मामला नहीं है।

3.5. जहां तक जीपीएफ का सवाल है, भंवर लाल (पति) के बैंक खाते (अनुलग्नक आर/3) में 3,09,160 रुपये की राशि जमा की गई थी और जवाब दाखिल करने के समय राज्य बीमा राशि भी उनके खाते में जमा करने के लिए संसाधित की जा रही थी।

3.6. भंवर लाल की सेवाओं की समाप्ति को उनके द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और केस फाइल की समीक्षा की है।

5. दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां एक कर्मचारी की पत्नी विधवा के बराबर पेंशन बकाया मांगती है। हालाँकि, यह न्यायालय नीचे बताए गए कारणों से ऐसी राहत नहीं दे सकता।

6. स्वीकार किया गया मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पति की सेवाएं 28.08.2015 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई थीं, जिससे पेंशन नियम, 1996 के नियम 23 के अनुसार उनकी पिछली सेवा जब्त हो गई थी।

7. परिणामस्वरूप, उनका परिवार किसी भी पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं है।

8. याचिकाकर्ता ने खुद दलील दी है कि उसके पति साधु बन गए और कई सालों तक काम पर नहीं आए। हालांकि, उनके साधु बनने के फैसले के लिए विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

9. मैं याचिकाकर्ता के इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकता कि उसके पति के साधु बनने के फैसले को मौत के समान माना जाना चाहिए। विभाग ने लागू सेवा नियमों के अनुसार काम किया है।

10. अंत में, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि मैं भी प्रतिवादियों के निर्विवाद जवाब में उनके रुख से सहमत हूं, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा कोई और हलफनामा या जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

11. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

12. याचिका खारिज की जाती है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।